दो दिन में विधायक की पानी समस्या खत्म!

- महापौर से गले मिले और शुभकामनाएं दी

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर में भीषण जल संकट की बात करने वाले विधायक महेंद्र हार्डिया के क्षेत्र में पानी की समस्या खत्म हो गई है. बताया जा रहा है कि हार्डिया का विरोध निजी टैंकर बंद होने के कारण ज्यादा था, जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित किए जा रहे थे. चर्चा है कि मामला महापौर के संज्ञान में आने के बाद टैंकरों पर रोक लगा दी गई. यही वजह विधायक ने मुद्दा बना दी.

शहर के विधानसभा 5 के विधायक महेंद्र हार्डिया ने दो दिन

पहले कहा कि शहर में भयंकर जल संकट पैदा हो गया है. स्थिति बहुत विस्फोटक है. लोग रोज सुबह मेरे घर आकर बैठ जाते हैं. मैं रोज सुबह महापौर निवास पर धरना दूंगा. कल दोनों विधायक रमेश मेंदोला और महेंद्र हार्डिया के साथ एमआईसी सदस्य राजेंद्र राठौर और राजेश उदावत ने बैठक की. कहा जा रहा है कि मीडिया में महापौर पुष्यमित्र भार्गव के खिलाफ बोलने के बाद हार्डिया को संगठन से लगाम कसी गई. संगठन ने इसे भाजपा सरकार विरोधी माना है. भोपाल से संगठन की हिदायत के बाद विधायक आज महापौर सचिवालय पहुंचे और गले में हाथ डाल कर कहा कि महापौर अच्छा काम कर रहे हैं. मेरे क्षेत्र की पानी की समस्या एक जो दिन में हल करने का कहा है. इसी के साथ विधानसभा 5 में जलसंकट की समस्या खत्म हो गई.

कांग्रेस का तंज

इंदौर के जलसंकट और बीजेपी विधायक महेंद्र हार्डिया के बदले सुरों पर अब कांग्रेस ने तंज कसा है. नगर निगम नेता प्रतिपक्ष और शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि यह जनता के हित की नहीं, बल्कि अधिकारों की लड़ाई है. चिंटू चौकसे ने कहा कि जब महेंद्र हार्डिया को लगा कि उनकी सुनवाई कम हो रही है, तो उन्होंने नाराजगी जता दी, लेकिन एक ही दिन में पलट भी गए. उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम से साफ हो गया है कि इंदौर के जनप्रतिनिधियों के लिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा जनहित से ऊपर है.

कलेक्टर की रोक के बावजूद कर दिया सीलिंग जमीन का नामांतरण

मामला बिचौली हप्सी का

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर की बिचौली हप्सी तहसील में तहसीलदार ने सीलिंग के जमीन का कलेक्टर की रोक होने के बावजूद नामांतरण कर दिया. शहर में सीलिंग जमीनों पर पूर्व कलेक्टर ने नामांतरण कर रोक लगाई थी और निर्देश जारी किए थे कि शहर में सीलिंग की जमीन बिना कलेक्टर से अनुमति लिए नामांतरण नहीं की जा सकती है.

मामला बिचौली हप्सी तहसील के ग्राम बिचोली की खसरा 34 /3/2से संबंधित जमीन का है, जिसकी रजिस्ट्री आशा जैन पति दिलीप जैन द्वारा वर्ष 2004 में कराई गई थी. 2004 से लेकर 2025 तक इसका नामांतरण किसी भी तहसीलदार द्वारा नहीं किया गया है. वर्ष 2022 में तत्कालीन कलेक्टर मनीषसिंह ने 1882/अ क री/2022 दिनांक 4.11.2022 में सीलिंग जमीनों के लेकर हस्तांतरण से पूर्व कलेक्टर की अनुमति आवश्यक होने का आदेश किया था. उक्त जमीन पूर्व में मां राजेश्वरी गृह निर्माण संस्था की रही है, जिसका खसरा नंबर 34 रकबा 9.940 हेक्टर सम्मिलित था, किंतु संस्था द्वारा सीलिंग की शर्तों का उल्लंघन कर उक्त जमीन रसूखदार व्यक्तियों को बेच दी गई. इसमें सीलिंग की धारा 20(5) की अनुमति नहीं थी. सीलिंग प्रकरण क्रमांक 2/अ/90 सी 19(5)/ 1988- 89 आदेश दिनांक 7-10-1989 के द्वारा संस्था को सीलिंग की धारा 19 के तहत छूट प्रदान की गई थी. आशा जैन द्वारा नामांतरण का आवेदन 20 साल बाद लगाया गया था. तहसीलदार द्वारा दिसंबर 2025 में निरस्त कर दिया गया, किंतु पुन: प्रकरण को शुरू करते हुए जनवरी 2026 में इसका आदेश कर दिया गया. प्रकरण को तहसीलदार द्वारा निरस्त करने के बाद एसडीएम कोर्ट में अपील की जानी चाहिए थी, किंतु तहसीलदार ने पुन: सुनवाई करते हुए आदेश पारित कर दिया.

20 साल तक नहीं किया नामांतरण

महत्वपूर्ण बात यह है कि उक्त जमीन की रजिस्ट्री का नामांतरण 20 साल से 15 तहसीलदारों द्वारा नहीं किया गया. उसे तत्कालीन तहसीलदार बलबीर सिंह राजपूत ने कर दिया. मामले का खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता केडी मिश्रा की शिकायत पर जांच में सामने आया है. तहसीलदार राजपूत की शिकायत मिलने पर पिछले महीने कलेक्टर द्वारा हटा दिया गया था. कलेक्टर के प्रतिबंधात्मक आदेश होने के बाद भी जमीन का नामांतरण कर दिया था.

एक नजर में

एनआईआईटी यूनिवर्सिटी ने प्रवेश की घोषणा की

इंदौर. एनआईआईटी यूनिवर्सिटी (एनयू) ने अपनी उत्कृष्टता के 15 वर्ष पूरे करते हुए 2026 के लिए प्रवेश की घोषणा कर दी है. छात्र सीयूईटी और इपमैट स्कोर के ज़रिए आवेदन करके एनयूएटी यानी एनआईआईटी यूनिवर्सिटी के एप्टीट्यूड टेस्ट से छूट पा सकते हैं और 100% तक छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं. प्रवेश प्रक्रिया के बारे में अपनी बात रखते हुए एनआईआईटी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट प्रोफेसर प्रकाश गोपालन ने कहा सीयूईटी और इपमैट स्कोर को स्वीकार करके हम छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाना चाहते हैं और इन प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में उनकी पहले से की गई मेहनत को मान्यता देना चाहते हैं. हमारा लक्ष्य है कि प्रेरित छात्रों को जल्द पहचाना जाए और उन्हें ऐक ऐसा माहौल दिया जाए जो मज़बूत अकादमिक आधार, इंडस्ट्री एक्सपोज़र और अनुभव आधारित शिक्षा को एक साथ जोड़ता हो.

इसुज़ु डी-मैक्स एस-कैब के लिए लीजिंग सॉल्यूशन पेश

इंदौर. इसुज़ु मोटर्स इंडिया ने इसुज़ु डी-मैक्स एस-कैब को लीज़ पर देने के एक नए मॉडल को पेश करने की घोषणा की. इसका उद्देश्य ग्राहकों को कमर्शियल वाहन खरीदने के बोझ के बिना, उनके इस्तेमाल का एक अधिक स्मार्ट और सुविधाजनक तरीका प्रदान करना है. इस पहल में मुख्य रूप से इसुज़ु डी-मैक्स एस-कैब को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि यह वाहन बेहद मजबूत और भरोसेमंद होने के साथ-साथ अलग-अलग तरह के व्यावसायिक कामों में इस्तेमाल किए जाने के लिए जाना जाता है. इस घोषणा के बारे में इसुज़ु मोटर्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश मित्तल ने कहा इसुज़ु पूरी दुनिया के अलग-अलग बाज़ारों में भरोसेमंद, टिकाऊ, व्यवसायों को आगे बढ़ाने में मददगार और बेहद कुशल कमर्शियल वाहन उपलब्ध कराने के लिए मशहूर है. हमने बेहतरीन गुणवत्ता वाली जापानी तकनीक और मजबूती मशहूर इसुज़ु के कमर्शियल वाहनों को उद्यमियों के लिए ज़्यादा सुलभ और आर्थिक रूप से ज़्यादा फायदेमंद बनाने के उद्देश्य से ही लीज़िंग विकल्प की शुरुआत की है.

द वेल्थ कंपनी लार्ज एंड मिड कैप फंड लांच

इंदौर. द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड ने अपने नए ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम द वेल्थ कंपनी लार्ज एंड मिड कैप फंड के लॉन्च की घोषणा की है. यह फंड लार्ज कैप और मिड कैप कंपनियों के शेयरों में निवेश करेगा. इस न्यू फंड ऑफर, यानी एनएफओ, की शुरुआत 21 मई से होगी और यह 4 जून 2026 तक खुला रहेगा. इस लॉन्च पर प्रतिक्रिया देते हुए द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड की फाउंडर, एमडी और सीईओ मधु लुनावत ने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां अलग-अलग क्षेत्रों में नेतृत्व तेजी से बदलता रहेगा. आने वाले समय में सबसे बेहतर अवसर उन कंपनियों में देखने को मिलेंगे जो टिकाऊ तरीके से विस्तार करने लगातार बेहतर प्रदर्शन देने और बदलते बाजार दौर के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता रखती हैं. इस फंड के जरिए कंपनी का उद्देश्य निवेशकों को लार्ज कैप कंपनियों की मजबूती और मिड कैप कंपनियों की ग्रोथ संभावनाओं का संतुलित लाभ देना है.

आपसी सहयोग का महत्व समझा रहा तारक मेहता का नया ट्रेक

इंदौर. तारक मेहता का उल्टा चश्मा की मौजूदा कहानी एक बार फिर दर्शकों को इंसानियत और आपसी सहयोग का महत्व समझा रही है. इस ट्रैक में रोशन सिंह सोढ़ी के एक दोस्त ने 15 दिनों के लिए सुरक्षित रखने हेतु उन्हें 1 लाख रुपये दिए होते हैं. लेकिन मिसेज रोशन सोढ़ी, कई वर्षों से परिचित एक फल विक्रेता की अचानक आर्थिक मदद की जरूरत को देखते हुए, वह रकम उसे दे देती हैं. फल विक्रेता तीन दिन में पैसे लौटाने का वादा करता है, लेकिन 15 वें दिन तक भी वह रकम का इंतजाम नहीं कर पाता. उसी रात सोढ़ी का दोस्त पैसे लेने आने वाला होता है, जिससे मिसेज सोढ़ी की परेशानी बढ़ जाती है. आखिरकार वह गोकुलधाम सोसायटी की महिला मंडल से मदद मांगती हैं और सभी महिलाएं तुरंत उनके साथ खड़ी हो जाती हैं, यह कहानी गोकुलधाम सोसायटी की महिलाओं के जरिए एकता, दया और इंसानियत की खूबसूरत मिसाल पेश करती है. यह ट्रैक निर्माता आसित कुमार मोदी की उस सोच को दर्शाता है, जिसमें मनोरंजन के साथ-साथ भारतीय संस्कारों और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी सार्थक कहानियां दिखाई जाती हैं.

स्वामी भास्करानंद के श्रीमुख से भागवत कथा 24 से

इंदौर. पुरुषोत्तम मास के पावन प्रसंग पर श्रीधाम वृन्दावन के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी भास्करानंद महाराज के श्रीमुख से श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव का दिव्य आयोजन 24 से 30 मई तक गीता भवन सत्संग सभागृह में आयोजित किया जा रहा है. महोत्सव का शुभारंभ गीता भवन परिसर में रविवार को दोपहर 2 बजे शोभा यात्रा के साथ होगा. इस दौरान अनेक उत्सव भी मनाए जाएँगे. आयोजन समिति के प्रमुख संयोजक संजय-किरण मंगल एवं बिनोद-सुनीता अग्रवाल ने बताया कि वरिष्ठ समाजसेवी प्रेमचंद गोयल, विष्णु बिंदल, राजेश चेलावत एवं श्याम अग्रवाल मोमबत्ती की प्रेरणा से पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में मातुश्री श्रीमती कमलादेवी-बाबूलाल मंगल की पुण्य स्मृति में यह दिव्य आयोजन किया जा रहा है.

भारतीय व्यवसायों के लिए दुबई की भूमिका हुई मजबूत

इंदौर. दुबई चैंबर्स के तहत संचालित तीन चैंबरों में से एक दुबई चैंबर ऑफ कॉमर्स ने घोषणा की है कि वर्ष 2026 की पहली तिमाही के दौरान 3,995 नई भारतीय कंपनियाँ चैंबर में शामिल हुई हैं. यह उल्लेखनीय वृद्धि चुनौतीपूर्ण वैश्विक व्यापारिक परिस्थितियों के बीच भारत और दुबई के बीच लगातार मजबूत होते आर्थिक और कारोबारी संबंधों को दर्शाती है. दुबई चैंबर्स के प्रेसिडेंट एवं सीईओ महामहिम मोहम्मद अली राशिद लूटा के मुताबिक तेजी से जटिल होती वैश्विक अर्थव्यवस्था में कंपनियाँ अब उन बाजारों को प्राथमिकता दे रही हैं, जो स्पष्ट नीतियाँ, भरोसेमंद कारोबारी माहौल और निरंतर विकास की क्षमता प्रदान करते हैं. भारतीय व्यवसायों की लगातार बढ़ती मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि वे दीर्घकालिक सफलता के लिए दुबई पर कितना विश्वास करते हैं. दुबई कंपनियों को विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, चुस्त कारोबारी वातावरण और वैश्विक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराता है, जिससे वे बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें.

स्कोडा ने अपने परफॉर्मेंस डीएनए को दी नई गति

इंदौर. तेज़ उत्पाद पहलों और निरंतर नेटवर्क विस्तार के बीच, स्कोडा ऑटो इंडिया ने स्कोडा की परफॉर्मेंस कहानी को मजबूती देने वाला अपना नवीनतम अभियान लॉन्च किया है. इस अभियान की शुरुआत एक रिकॉर्ड के साथ की गई है, जो उन कई पहलों में से एक है, जो यह साबित करती हैं कि 'ग्रेटेस्ट ऑन अ ट्रैक' वास्तव में 'ट्रैक पर स्कोडा' है. इस अभियान के बारे में बात करते हुए, स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर आशिष गुप्ता ने कहा हर स्कोडा को परफॉर्मेंस के उच्चतम स्तर पर सटीकता, नियंत्रण और बेहतरीन डायनेमिक्स प्रदान करने के लिए इंजीनियर किया गया है. हमारे लिए मोटरस्पोर्ट डीएनए केवल एक पहचान नहीं है, बल्कि यह हमारी हर कार का स्वाभाविक हिस्सा है और हमारी पूरी वाहन श्रृंखला में मानक रूप से मौजूद है. यही विश्वास हमारे इस नए अभियान की नींव है, जिसमें हम 'ग्रेटेस्ट ऑन अ ट्रैक' को एक नया अर्थ दे रहे हैं- और इसका सीधा अर्थ है, 'ट्रैक पर स्कोडा'. यह अभियान परफॉर्मेंस को सभी के लिए सुलभ बनाने की हमारी रणनीति का स्वाभाविक विस्तार है- यह सुनिश्चित करते हुए कि हर सेगमेंट में हर स्कोडा बेहतरीन डायनेमिक क्षमता, सुरक्षा और आत्मविश्वास प्रदान करती है, जिन्हें वास्तविक ड्राइविंग अनुभव में सहज रूप से महसूस किया जा सकता है.

आज हालत बदल गए, कार्यकर्ता हमको नहीं पहचानते

- पूर्व मंत्री अजय सिंह ने गांधी भवन में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक

नव भारत न्यूज

इंदौर. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अजयसिंह ने आज गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. बैठक में सिंह ने कांग्रेस सरकार की जनहित की योजनाओं को बताया और कहा कि कांग्रेस के काम की तुलना में भाजपा कहीं भी नहीं है. फिर बोले आज हालत बदल गए है, आज कार्यकर्ता ही हमको नहीं पहचानते हैं.

पूर्व मंत्री और 7 बार के कांग्रेस विधायक अजय सिंह आज दो दिन के इंदौर प्रवास पर आए. आज गांधी भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बताया कि देश में गरीबों को आवास के पट्टे इंदिरा गांधी ने दिए थे और उनको नियमित पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह ने किया था. कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से नेता और मंत्रियों का सीधा और परिवार का नाता था. आज कार्यकर्ता ही नहीं पहचानते हैं. उन्होंने एक कार्यकर्ता से पूछा कि तो उसने बताया सीधी से हूं. उन्होंने कहा कि यह मेरे क्षेत्र से है और मुझे नहीं पहचानता है. सिंह पूछा मैं मंत्री था मालूम है? उसने मना कर दिया है नहीं मालूम. सिंह ने भाजपा को उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की पार्टी कहते हुए तंज कसा कि आज प्रदेश और देश के हालत गंभीर है. स्थिति बहुत खराब है और आने वाले समय चिंताजनक स्थिति बनेगी. उन्होंने कार्यकर्ताओं से दोहराया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार फिर बनेगी और आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा. युवाओं को अब आगे आना जरूरी है. मेरी उम्र 72 साल की हो गई है और चुनाव तक 74-75 हो जाएगी. कांग्रेस में गद्दारों की कोई जगह नहीं है. वक्त आने पर गद्दारों को भी सबक सिखाया जाएगा. बैठक में शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े, प्रवक्ता राजेश चौकसे, पार्षद राजू भदौरिया, सोनीला मिमरोट भाटिया, यशस्वी पटेल, प्रवेश यादव, अभिषेक शर्मा बिट्टू, दिनेश मल्हार, जय हार्डिया, पूर्व युवक कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे. संचालन शैलेश गर्ग ने किया. आभार पार्षद कुणाल सोलंकी ने माना.

सिंधिया वापस आए तो कांग्रेस छोड़ दूंगा : अजयसिंह

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री और 7 बार के विधायक अजायसिंह ने कहा कि यदि सिंधिया वापस कांग्रेस में लिए गए, तो मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा. सिंह ने यह बात वरिष्ठ शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रवेश यादव द्वारा पूछने पर कि गद्दारों के विषय में आपका क्या कहना है, यदि वे कांग्रेस मैं वापसी करते है. इस पर अजयसिंह ने कहा कि गद्दारों की कांग्रेस में कोई जगह नहीं है. सिंधिया को वापस कांग्रेस में लाया गया तो मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ दूंगा. इसके बाद अजयसिंह ने यह भी कहा कि किसी का क्षेत्रीय जनाधार और जनता के बीच चेहरा अपील करता है तो उसका स्वागत भी कांग्रेस में करेंगे.

ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ केमिस्टों की हड़ताल

- बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा बिक्री पर सख्ती की मांग
- केमिस्टों का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन

नवभारत न्यूज

इंदौर. इंदौर अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री, बिना प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की होम डिलीवरी और भारी छूट के जरिए दवा कारोबार में बढ़ते अनियंत्रण के विरोध में मंगलवार को इंदौर सहित देशभर के केमिस्टों ने एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की.

इस दौरान अधिकांश दवा दुकानें बंद रहीं और संबंधित प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया. यह आंदोलन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स तथा मध्य प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के आह्वान पर किया गया, जिसमें इंदौर जिले के सैकड़ों केमिस्ट और दवा विक्रेताओं ने भाग लिया. ज्ञापन में कहा गया कि बिना वैध और सत्यापित ई-प्रिस्क्रिप्शन के दवाओं की बिक्री, फर्जी प्रिस्क्रिप्शन का उपयोग और बिना चिकित्सकीय परामर्श दवा वितरण जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुका है. केमिस्टों का कहना है कि इससे देशभर के लाखों लाइसेंसधारी छोटे दवा व्यापारियों के अस्तित्व पर भी संकट खड़ा हो रहा है. दवा विक्रेताओं ने आरोप लगाया कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और नियम 1945 में ऑनलाइन दवा बिक्री को लेकर स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं, इसके बावजूद कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लगातार दवा बिक्री कर रहे हैं. उन्होंने वर्ष 2018 की अधिसूचना जीएसआर 817(ई) को अप्रासंगिक बताते हुए तथा कोविड काल में जारी जीएसआर 220(ई) के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि इनका इस्तेमाल अब सामान्य परिस्थितियों में अनियंत्रित ऑनलाइन डिलीवरी के लिए किया जा रहा है. केमिस्ट संगठनों ने सरकार से अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री पर तत्काल सख्त कार्रवाई, बिना सत्यापित ई-प्रिस्क्रिप्शन दवा बिक्री और होम डिलीवरी पर पूर्ण प्रतिबंध, जीएसआर 817(ई) और जीएसआर 220(ई) की वापसी तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की अत्यधिक छूट और नीति पर रोक लगाने की मांग की है.

ठोस कार्रवाई नहीं तो आंदोलन तेज होगा

साथ ही कहा गया कि दवा विक्रेता देश की स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्था की रीढ़ हैं और कोविड महामारी के दौरान भी उन्होंने निर्बाध दवा आपूर्ति सुनिश्चित की थी. संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

विद्युत पेंशनर्स हित रक्षक संघ का प्रदर्शन

- पेंशनर्स ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा

नवभारत न्यूज

इंदौर. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी प्रबंधन के कथित पेंशनर्स विरोधी रवैये और लंबित मांगों के विरोध में बुधवार को विद्युत पेंशनर्स हित रक्षक संघ ने जोरदार धरना-प्रदर्शन किया. प्रदर्शन जीपीएच परिसर, पोलोग्राउंड स्थित पश्चिमी क्षेत्र विद्युत कंपनी मुख्यालय के मुख्य द्वार पर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया गया.

धरने में प्रदेशभर की 45 शाखाओं से आए बड़ी संख्या में पेंशनर्स, पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए. भीषण गर्मी के बावजूद वृद्ध पेंशनर्स ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई. संघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि संगठन द्वारा कई बार मुख्यमंत्री मोहन यादव, ऊर्जा मंत्री और ऊर्जा सचिव को पत्र लिखकर पेंशनर्स की समस्याओं के निराकरण तथा ठोस निर्णय की मांग की जा चुकी है, लेकिन अब तक कई महत्वपूर्ण मांगें लंबित हैं.

इसी के विरोध में यह आंदोलन आयोजित किया गया. प्रदर्शन के दौरान पेंशनर्स ने कंपनी प्रबंधन पर उपेक्षापूर्ण और हिटलरशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया तथा चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा. धरना-प्रदर्शन में प्रमुख रूप से आरडी मिश्रा, शिव बहादुर सिंह ठाकुर, केके पुरोहित, आशुतोष अवस्थी, भीम सेन सिंह, एस. एन. पटेल, आर. बी. बैस, बी. एल. पटेल, दिनेश डाले एवं विजय कुमार राठौर उपस्थित रहे.

बिजली कंपनी की कमर्शियल वसूली व्यवस्था पर सवाल

- एक लाख बकायादारों पर 50 करोड़ बकाया

नवभारत न्यूज

इंदौर. मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की कमर्शियल श्रेणी में राजस्व वसूली की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है. विभागीय समीक्षा बैठक में यह सामने आया कि दुकानें, मॉल, लघु उद्योग, आटा चक्की और शोरूम जैसे गैर घरेलू उपभोक्ताओं के करीब एक लाख कनेक्शनों पर लगभग 50 करोड़ रुपये से अधिक की बिजली बिल राशि बकाया है. लगातार बढ़ते बकाए ने विभाग की कार्यप्रणाली और वसूली तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

बुधवार को हुई समीक्षा बैठक में कंपनी के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए मई के शेष दिनों में हर हाल में वसूली अभियान तेज करने के निर्देश दिए. उन्होंने साफ कहा कि समय पर बिल वसूली विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों से साप्ताहिक रिपोर्ट भी मांगी गई है, जिससे साफ है कि विभाग वसूली लक्ष्य पूरे नहीं होने से दबाव में है.

सूत्रों के अनुसार लंबे समय से कमर्शियल उपभोक्ताओं से बकाया वसूली प्रभावी ढंग से नहीं हो पाने के कारण विभाग की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है. सवाल यह भी उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में बकायादार बनने तक विभागीय अमला क्या कर रहा था. अब अचानक मई के अंतिम दिनों में बड़े पैमाने पर वसूली के निर्देश जारी होने से विभाग की तैयारी और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं. विभागीय हलकों में चर्चा है कि लगातार बढ़ते कमर्शियल बकाए और धीमी वसूली ने कंपनी प्रबंधन की चिंता बढ़ा दी है. आने वाले दिनों में बड़े बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कनेक्शन काटने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं.

शिकायतों के निराकरण में देरी पर नाराजगी

बैठक में 1912 कॉल सेंटर और अन्य माध्यमों से आने वाली शिकायतों के निराकरण में देरी पर भी नाराजगी जताई गई. शहरों में एक से दो घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में दो से चार घंटे में शिकायतें हल करने के निर्देश दिए गए. इससे यह संकेत भी मिला कि उपभोक्ता शिकायतों के समाधान में अपेक्षित गति नहीं है. इसके अलावा खराब मीटर बदलने, लाइन मेंटेनेंस, आरडीएसएस और एसएसटीडी परियोजनाओं के कार्यों में देरी को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए. बारिश से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था सुधारने के आदेश दिए गए हैं.

एक नजर में

ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक आयोजित

ब्रिक्स युवा उद्यमिता बैठक में जनसांख्यिकीय ताकत से भविष्य गढ़ने पर जोर

नवभारत न्यूज

इंदौर. इंदौर भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत इंदौर में आयोजित ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक में युवा-नेतृत्व वाले नवाचार, स्टार्टअप सहयोग और सतत विकास पर व्यापक चर्चा हुई. बैठक का विषय 'लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण' रखा गया है. इसमें ब्रिक्स देशों के युवा उद्यमी, नीति-निर्माता, स्टार्टअप लीडर्स और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए.

केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिक्स देशों की जनसांख्यिकीय शक्ति उन्हें वैश्विक कार्य संस्कृति और रोजगार के भविष्य को आकार देने का अवसर देती है. उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों की संयुक्त आबादी दुनिया की

लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है और कई सदस्य देशों में 35 वर्ष से कम आयु की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है. भारत में लगभग 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, जो नवाचार और उद्यमिता की बड़ी ताकत है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में कौशल विकास, डिजिटल समावेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम में हुई प्रगति का उल्लेख किया. युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे ने कहा कि जब ब्रिक्स देश मिलकर काम करते हैं और एक-दूसरे से सीखते हैं, तब स्थानीय नवाचार वैश्विक प्रभाव पैदा करते हैं. उन्होंने कहा कि भारत के छोटे शहरों और टियर-2 एवं टियर-3 शहरों के युवा तेजी से सफल उद्यम स्थापित कर रहे हैं, जो समावेशी और युवा-नेतृत्व वाले विकास का उदाहरण है. बैठक में डिजिटल नवाचार, एआई, फिनटेक, एग्रीटेक, हरित उद्यमिता, स्वच्छ ऊर्जा और सामाजिक उद्यमिता जैसे विषयों पर पैनल चर्चा आयोजित की गई। कार्यक्रम में प्रदर्शनी, नेटवर्किंग सत्र, फायरसाइड वार्ता और संवादात्मक कार्यशालाएं भी आयोजित हुईं, जिनका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के युवा उद्यमियों के बीच सहयोग और साझेदारी को मजबूत करना है।

नवाचार, रोजगार की प्रमुख शक्ति-युवा कार्यक्रम विभाग की - सचिव पल्लवी जैन गोविल ने कहा कि युवा उद्यमिता अब नवाचार, रोजगार और समावेशी विकास की प्रमुख शक्ति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स उद्यमिता कार्य समूह सदस्य देशों को अनुभव साझा करने और भविष्य के लिए तैयार उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है.

मप्र निवेश का प्रमुख केंद्र : सारंग

मध्यप्रदेश शासन के सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ब्रिक्स राष्ट्र नवाचार, उद्यमिता और वैश्विक सहयोग के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं. ब्रिक्स अब केवल आर्थिक गठबंधन नहीं, बल्कि व्यापार, तकनीक और सतत विकास को दिशा देने वाला वैश्विक मंच बन चुका है. उन्होंने बताया कि ब्रिक्स समूह विश्व की लगभग आधी आबादी और वैश्विक जीडीपी के 35 से 40 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है. विश्वास सारंग ने कहा कि मध्यप्रदेश निवेश, औद्योगिक विकास और स्टार्टअप ग्रोथ का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है. उन्होंने इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर और मध्य भारत का इनोवेशन हब बताते हुए राज्य की आईटी, एग्रीटेक, रिन्यूएबल एनर्जी और स्टार्टअप संभावनाओं को रेखांकित किया.